OVERVIEW

This chapter examines the growing significance of environmental as well as resource issues in world politics. It analyses in a comparative perspective some of the important environmental movements against the backdrop of the rising profile of environmentalism from the 1960s onwards. Notions of common property resources and the global commons too are assessed.

इस अध्याय में विश्व–राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्त्व की चर्चा की गई है। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्त्वपूर्ण पर्यावरण–आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है। हम साझी संपदा और 'विश्व की साझी विरासत' जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे।

We also discuss, in brief, the stand taken by India in more recent environmental debates. Next follows a brief account of the geopolitics of resource competition. We conclude by taking note of the indigenous peoples' voices and concerns from the margins of contemporary world politics.

इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल की बहसों में भारत ने कौन–सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। अध्याय का समापन यह बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व–राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता (**Indigenous people**) के इन सवालों से क्या सरोकार हैं और वह क्या सोचती है।

OVERVIEW

अराल के आसपास बसे हज़ारों लोगों को अपना घर–बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य–उद्योग नष्ट हो गया। जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता के ज़्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए लेकिन इस समस्या का समाधान न हो सका। दरअसल इस जगह मज़ाक–मज़ाक में लोग एक–दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आये वे अगर एक–एक बाल्टी पानी भी लाते तो यह सागर भर गया होता।

वैश्विक तापवृद्धि

यहाँ अंगुलियों को चिमनी और विश्व को एक लाईटर के रूप में दिखाया गया है। ऐसा क्यों?

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

Throughout the world, cultivable area is barely expanding any more, and a substantial portion of existing agricultural land is losing fertility. Grasslands have been overgrazed and fisheries overharvested. Water bodies have suffered extensive depletion and pollution, severely restricting food production.

दुनिया भर में कृषि–योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य–भंडार घट रहा है। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है उसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य– उत्पादन में कमी आ रही है।

According to the *Human Development Report 2016 of the* United Nations Development Programme, 663 million people in developing countries have no access to safe water and 2.4 billion have no access to sanitation, resulting in the death of more than three million children every year.

संयुक्त राष्ट्रसंघ की *मानव विकास रिपोर्ट* (2016) के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहां की दो अरब चालीस करोड आबादी साफ़-सफ़ाई की सुविधा से वंचित हैं। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं।

Natural forests — which help stabilise the climate, moderate water supplies, and harbour a majority of the planet's biodiversity on land—are being cut down and people are being displaced. The loss of biodiversity continues due to the destruction of habitat in areas which are rich in species.

प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इनसे जलचक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव-विविधता का भंडार भरा रहता है लेकिन एसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव-विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव-प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं।

A steady decline in the total amount of ozone in the Earth's stratosphere (commonly referred to as the ozone hole) poses a real danger to ecosystems and human health.

धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओज़ोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओज़ोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

Coastal pollution too is increasing globally. Although the open sea is relatively clean, the coastal waters are becoming increasingly polluted largely due to land-based activities. If unchecked, intensive human settlement of coastal zones across the globe will lead to further deterioration in the quality of marine environment.

पूरे विश्व में समुद्रतटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्रतटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

You might ask are we not talking here about 'natural phenomena' that should be studied in geography rather than in political science. But think about it again. If the various governments take steps to check environmental degradation of the kind mentioned above, these issues will have political consequences in that sense.

आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएँ हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। लेकिन ज़रा फिर से सोचिए। पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

Most of them are such that no single government can address them fully. Therefore they have to become part of 'world politics'. Issues of environment and natural resources are political in another deeper sense. Who causes environmental degradation? Who pays the price?

इन मसलों में अधिकांष्टा एसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व–राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है? इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है?

And who is responsible for taking corrective action? Who gets to use how much of the natural resources of the Earth? All these raise the issue of who wields how much power. They are, therefore, deeply political questions.

धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

Although environmental concerns have a long history, awareness of the environmental consequences of economic growth acquired an increasingly political character from the 1960s onwards. The Club of Rome, a global think tank, published a book in 1972 entitled *Limits to Growth*, dramatising the potential depletion of the Earth's resources against the backdrop of rapidly growing world population.

हालाँकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत् समूह 'क्लब ऑव रोम' ने 1972 में 'लिमिट्स टू ग्रोथ' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

International agencies, including the United Nations Environment Programme (UNEP), began holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems. Since then, the environment has emerged as a significant issue of global politics.

संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराये और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण मसला बन गया।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

The growing focus on environmental issues within the arena of global politics was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil, in June 1992. This was also called the Earth Summit. The summit was attended by 170 states, thousands of NGOs and many multinational corporations.

1992 में संयुक्त राष्ट्रसंघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हज़ारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला।

Five years earlier, the 1987 Brundtland Report, *Our Common Future, had warned that* traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially in view of the demands of the South for further industrial development.

इस सम्मेलन से पाँच साल पहले (1987) 'अवर कॉमन फ्यूचर' शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर–तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की माँग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

What was obvious at the Rio Summit was that the rich and developed countries of the First World, generally referred to as the 'global North' were pursuing a different environmental agenda than the poor and developing countries of the Third World, called the 'global South'. Whereas the Northern states were concerned with ozone depletion and global warming, the Southern states were anxious to address the relationship between economic development and environmental management.

रियो–सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आयी कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्द्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्द्ध पर्यावरण के अलग–अलग अजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओज़ोन परत की छेद और वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वमिंग) को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे।

The Rio Summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity, forestry, and recommended a list of development practices called 'Agenda 21'. But it left unresolved considerable differences and difficulties. There was a consensus on combining economic growth with ecological responsibility. This approach to development is commonly known as 'sustainable development'.

रियो–सम्मेलन में जलवायु–परिवर्तन, जैव–विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें 'अजेंडा–21' के रूप में विकास के कुछ तौर–तरीके भी सुझाए गए। लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रहीं। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका एसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। इसे 'टिकाऊ विकास' का तरीका कहा गया।

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN GLOBAL POLITICS

The problem however was how exactly this was to be achieved. Some critics have pointed out that Agenda 21 was biased in favour of economic growth rather than ensuring ecological conservation. Let us look at some of the contentious issues in the global politics of environment.

लेकिन समस्या यह थी कि 'टिकाऊ विकास' पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि 'अजेंडा–21' का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए, अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं।

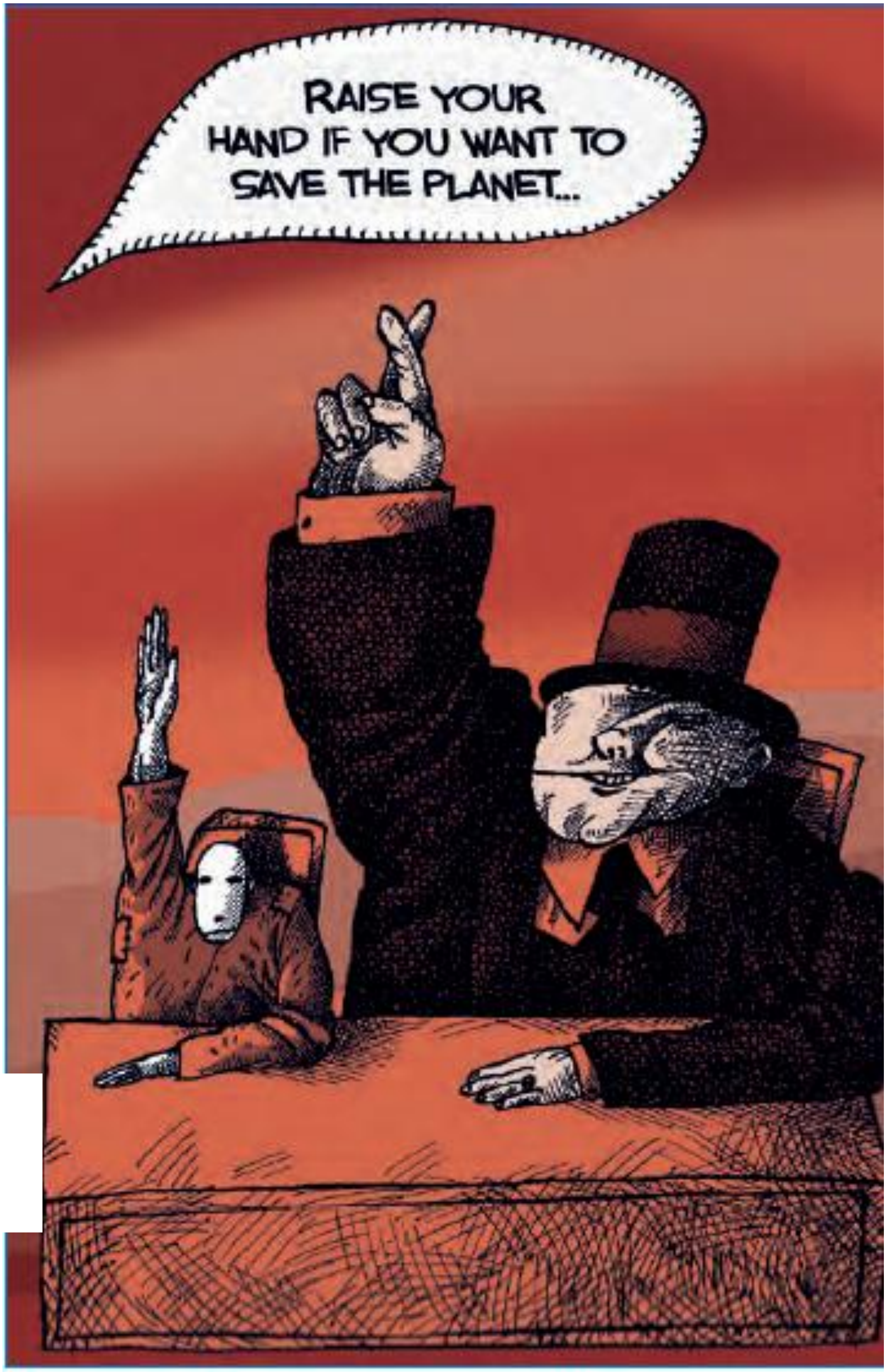

क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नज़रिए में अंतर है?

THE PROTECTION OF GLOBAL COMMONS

‘Commons’ are those resources which are not owned by anyone but rather shared by a community. This could be a ‘common room’, a ‘community centre’, a park or a river. Similarly, there are some areas or regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state, and therefore require common governance by the international community.

साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है।

THE PROTECTION OF GLOBAL COMMONS

These are known as *res communis humanitatis or global commons. They include the* earth's atmosphere, Antarctica (see Box), the ocean floor, and outer space. Cooperation over the global commons is not easy. There have been many path-breaking agreements such as the 1959 Antarctic Treaty, the 1987 Montreal Protocol, and the 1991 Antarctic Environmental Protocol.

इन्हें 'वैश्विक संपदा' या 'मानवता की साझी विरासत' कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। 'वैश्विक संपदा' की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि (1959), मांटियल न्यायाचार (प्रोटोकॉल 1987) और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार (1991) हो चुके हैं।

THE PROTECTION OF GLOBAL COMMONS

A major problem underlying all ecological issues relates to the difficulty of achieving consensus on common environmental agendas on the basis of vague scientific evidence and time frames. In that sense the discovery of the ozone hole over the Antarctic in the mid-1980s revealed the opportunity as well as dangers inherent in tackling global environmental problems.

पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय–सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। एसे में एक सर्व–सामान्य पर्यावरणीय अजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है।

THE PROTECTION OF GLOBAL COMMONS

Similarly, the history of outer space as a global commons shows that the management of these areas is thoroughly influenced by North-South inequalities. As with the earth's atmosphere and the ocean floor, the crucial issue here is technology and industrial development. This is important because the benefits of exploitative activities in outer space are far from being equal either for the present or future generations.

ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहां भी महत्त्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक ज़रूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन-कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न आगे की पीढ़ियों के लिए।

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES

We have noted above a difference in the approach to environment between the countries of the North and the South. The developed countries of the North want to discuss the environmental issue as it stands now and want everyone to be equally responsible for ecological conservation.

ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है।

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES

The developing countries of the South feel that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed countries. If they have caused more degradation, they must also take more responsibility for undoing the damage now. Moreover, the developing countries are in the process of industrialisation and they must not be subjected to the same restrictions, which apply to the developed countries.

दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुँचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा, विकासशील देश अभी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगें जो विकसित देशों पर लगाये जाने हैं।

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES

Thus the special needs of the developing countries must be taken into account in the development, application, and interpretation of rules of international environmental law. This argument was accepted in the Rio Declaration at the Earth Summit in 1992 and is called the principle of 'common but differentiated responsibilities'.

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सन् 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे 'साझी परंतु अलग–अलग जिम्मेदारियां' का सिद्धांत कहा गया।

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES

The relevant part of the Rio Declaration says that "States shall cooperate in the spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions of global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities.

इस संदर्भ में रियो–घोषणापत्र का कहना है कि µ ¶/रती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व–बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग–अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की 'साझी परंतु अलग–अलग जिम्मेदारियां' होगी।

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES

The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technological and financial resources they command.”

विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन हैं। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी ख़ास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।’’

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES

The 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) also provides that the parties should act to protect the climate system "on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities."

जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्रसंघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज **(UNFCCC-1992)** में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देष्टा अपनी क्षमता के अनुरूप, पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग–अलग ज़िम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे।

COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES

Certain gases like Carbon dioxide, Methane, Hydro-fluoro carbons etc. are considered at least partly responsible for global warming - the rise in global temperature which may have catastrophic consequences for life on Earth. The protocol was agreed to in 1997 in Kyoto in Japan, based on principles set out in UNFCCC.

ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांतों तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

India signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol in August 2002. India, China and other developing countries were exempt from the requirements of the Kyoto Protocol because their contribution to the emission of greenhouse gases during the industrialisation period (that is believed to be causing today's global warming and climate change) was not significant.

भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगीकरण के दौर में ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्ज़न के मामले में इनका कुछ ख़ास योगदान नहीं था। औद्योगीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु–परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

However, the critics of the Kyoto Protocol point out that sooner or later, both India and China, along with other developing countries, will be among the leading countributors to greenhouse gas emissions. At the G-8 meeting in June 2005, India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world.

बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्ज़न के मामले में विकसित देशों की भाँति अगली कतार में नज़र आयेंगे। 2005 के जून में ग्रुप-8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाऊस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

Following the principle of common but differentiated responsibilities, India is of the view that the major responsibility of curbing emission rests with the developed countries, which have accumulated emissions over a long period of time.

साझी परंतु अलग–अलग ज़िम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन–दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी विकसित देशों की है क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

India's international negotiating position relies heavily on principles of historical responsibility, as enshrined in UNFCCC. This acknowledges that developed countries are responsible for most historical and current greenhouse gas emissions, and emphasizes that 'economic and social development are the first and overriding priorities of the developing country parties'.

संयुक्त राष्ट्रसंघ के जलवायु–परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC) के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर एतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीनहाऊस गैसों के रिसाव की एतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि 'विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है।'

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

So India is wary of recent discussions within UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly industrialising countries (such as Brazil, China and India) to reduce their greenhouse gas emissions. India feels this contravenes the very spirit of UNFCCC. Neither does it seem fair to impose restrictions on India when the country's rise in per capita carbon emissions by 2030 is likely to still represent less than half the world average of 3.8 tonnes in 2000. Indian emissions are predicted to rise from 0.9 tonnes per capita in 2000 to 1.6 tonnes per capita in 2030.

हाल में संयुक्त राष्ट्रसंघ के इस नियमाचार (UNFCCC) के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश (जैसेइ ब्राजील, चीन और भारत) नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के (सन् 2000) के औसत (3.8 टन प्रति व्यक्ति) के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रतिव्यक्ति हो जाएगी।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

The Indian government is already participating in global efforts through a number of programmes. For example, India's National Auto-fuel Policy mandates cleaner fuels for vehicles. The Energy Conservation Act, passed in 2001, outlines initiatives to improve energy efficiency. Similarly, the Electricity Act of 2003 encourages the use of renewable energy.

भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो–फ्यूल पॉलिसी' के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर इंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा–संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा (त्मदमूंइसम) ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

Recent trends in importing natural gas and encouraging the adoption of clean coal technologies show that India has been making real efforts. The government is also keen to launch a National Mission on Biodiesel, using about 11 million hectares of land to produce biodiesel by 2011–2012. And India has one of the largest renewable energy programmes in the world.

हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011–12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

A review of the implementation of the agreements at the Earth Summit in Rio was undertaken by India in 1997. One of the key conclusions was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally-sound technology on concessional terms to developing nations.

भारत ने पृथ्वी–सम्मेलन (रियो) के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नये और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है।

INDIA'S STAND ON ENVIRONMENTAL ISSUES

India finds it necessary that developed countries take immediate measures to provide developing countries with financial resources and clean technologies to enable them to meet their existing commitments under UNFCCC. India is also of the view that the SAARC countries should adopt a common position on major global environment issues, so that the region's voice carries greater weight.

भारत इस बात को ज़रूरी मानता है कि विकसित देष्टा विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश 'फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज' की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। भारत का यह भी मानना है कि 'दक्षेस' (SAARC) में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनायें ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वज़नी हो सके।

ENVIRONMENTAL MOVEMENTS: ONE OR MANY?

We have, so far, looked at the way governments have reacted at the international level to the challenge of environmental degradation. But some of the most significant responses to this challenge have come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world. Some of them work at the international level, but most of them work at the local level.

पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निबटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है हम उस के बारे में जान चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्त्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की हैं। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं।

ENVIRONMENTAL MOVEMENTS: ONE OR MANY?

These environmental movements are amongst the most vibrant, diverse, and powerful social movements across the globe today. It is within social movements that new forms of political action are born or reinvented. These movements raise new ideas and long-term visions of what we should do and what we should not do in our individual and collective lives. Here are just a few examples to show that diversity is an important trait of contemporary environmental movements.

आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नये रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहां कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है।

ENVIRONMENTAL MOVEMENTS: ONE OR MANY?

The forest movements of the South, in Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, continental Africa and India (just to list a few examples) are faced with enormous pressures. Forest clearing in the Third World continues at an alarming rate, despite three decades of environmental activism. The destruction of the world's last remaining grand forests has actually increased in the last decade.

दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन–आंदोलनों पर बहुत दबाव है। तीन दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है।